Sl. No.	Project	Total aid Proposed (Million US $)
5	Lube Revamp at Haldia	10
6	Sulphur Plant at Haldia	1
7	Single Buoy Mooring System at Salaya	12
8	Distributed Digital Control Systems for Refineries	45
9	Yield & Energy Optimisation	17
10	Technical Assistance and Training for Refineries and Pipelines	10
		340

(c) and (d) The decision to sign the loan agreement with World Bank pending approval of the projects was taken keeping in view that the loan offers are not open for indefinite time and the World Bank could not be asked to wait till all the listed projects were formally approved by the Government.

(e) and (f) IOC paid commitment charges of Rs. 4.98 crores during this period. However, this payment is not infructuous as the same is a part of normal financing arrangements with World Bank and is payable on the loan amount not drawn.

(g) Government has taken a decision in March 1993 to cancel a part of loan of $ 290 million out of $ 340 million. IOC had withdrawn a Revolving fund of $ 35 million out of which about $ 7.5 million has actually been utilised. Undrawn loan remains at $ 15 million, on which commitment charges are payable.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लाभ में कमी

1818. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लाभ में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घटते लाभ के संबंध में प्रबंधन की भूमिका के बारे में कोई समीक्षा की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का शुद्ध लाभ वर्ष 1989-90 में हुये 1624 करोड़ रूपये से घटकर 1990-91 में 1048 करोड़ रुपये और 1991-92 में 408 करोड़ रुपये हो गया । इनके कारणों में ये बातें शामिल है रुपये तथा प्रमुख विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर में लगातार परिवर्तन होने से हानि, बढ़ा हुआ प्रचालन व्यय, सूखे कूपों पर वर्धित प्रभार तथा उत्पादन अवयक की क्षीणता, वर्धित ब्याज प्रभार तथा वर्धित निगम कर ।

(ग) और (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य-कलाप की पुनरीक्षा करने के लिये सरकार ने श्री पी० के० कौल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया । कंपनी अधिनियम के अधीन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में बदलने तथा नई कम्पनी में 20 प्रतिशत इक्विटी पर अधिकार खोने की समिति

की अनुशंसाओं को सरकार ने स्वीकार कर लिया है । सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को दी जाने वाली कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की शासित कीमत में क्रमशः 15-9-1992 तथा 1-1-1992 से संशोधन भी किया है ।

मध्य भारत में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

1819. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य भारत में संयुक्त उपक्रम के रूप में 6 एम टी प्रतिवर्ष क्षमता का तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम के स्थल के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) इस संबंध में कितने प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने आठवीं/नौवीं योजना के दौरान मध्य भारत में संयुक्त क्षेत्र में 6 एम एम टी पी ए क्षमता की तेल रिफाइनर की स्थापना के लिये सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है । भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने इस उद्देश्य के लिये मैसर्स ओमान आयल कम्पनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है । संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा रिफाइनरी के अंतिम स्थान का निर्णय किया जाना है ।

विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करने और आरम्भिक व्यय करने की दृष्टि से सरकार ने 19.70 करोड़ रुपये खर्च करने के लिये भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत भी किया है ।

Oil reserves in the country

1820. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that oil reserves of India are likely to get exhausted within 25 to 30 years; the details thereof;

(b) whether it is also a fact that there is no significant increase in the inventory of oil reserves; if so, the reasons thereof;

(c) whether Government contemplate a long-term strategy to meet this situation; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) At the current rate of production the established balance recoverable reserves in the country would last for about 30 years. However, this does not take into account the accretion to reserves through exploration during the same period.

(b) to (d) Accretion to recoverablt reserves has more than offset the depletion of reserves through production in the Sixth and Seventh plan periods. Since incremental accretion becomes progressively more difficult it requires more sophisticated techniques and greater investment of resources in exploration effort. To supplement the efforts of the national oil companies, Government has decided to offer acreage for exploration to private companies on a continuous round-the-year basis. Accordingly 45 blocks have been offered under the Fifth Round of Bidding, the last date for submission of offers under which is 30th June, 1993.